RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 03 JUNE TO 09 JUNE 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 41 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

एमएसएमई: 20 हजार करोड़ रुपये की ऋण सहायता, 50 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंजूरी
Page 3

सेवा क्षेत्र गतिविधियों में मई में गिरावट, कंपनियां घटा रही हैं नैकरियां: सर्वे
Page 4

सरकार ने 2020-21 के लिये धान के एमएसपी में 53 रुपये की वृद्धि की
Page 7

editoria!

बुरे बेस-ईयर पर मंदी

देश की जीडीपी ग्रोथ रेट के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले भले न हों, पर चिंतित करने वाले जरूर हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही जनवरी से मार्च में विकास दर लुढ़क कर 3.1 फीसदी पर आ गई। पूरे साल के लिए यह 4.2 फीसदी निकली है जो 2018-19 के 6.1 फीसदी से तो काफी नीचे है ही, पिछले 11 साल का सबसे निचला स्तर भी है। ध्यान रहे, ये आंकड़े कोरोना की महामारी और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था को लगे झटकों से ठीक पहले का हाल बयान करते हैं। यूं कहें कि इनसे हमारे सामने नई मंदी के आधार वर्ष का खाका खिंचता है। लॉकडाउन का फैसला मार्च के आखिरी हफ्ते में आया, यानी करीब-करीब वह पूरी तिमाही कोरोना इंपैक्ट से बची रही। इसके बावजूद आंकड़े इतने निराशाजनक हैं तो इससे सिर्फ यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बीमारी को आगे सिर्फ कोरोना से जोड़कर न देखा जाए। हम जानते हैं कि हमारी इकॉनमी काफी पहले से सुस्ती की शिकार थी। जून 2018 के बाद से यह लगातार सातवीं तिमाही है जब विकास दर या तो नीचे की ओर गई या लगभग स्थिर रही। इसके बरक्स सरकार के रवैये पर ध्यान दें तो उसकी ओर से कभी ऐसा कुछ ठोस नहीं कहा गया, जिससे पता चलता कि अर्थव्यवस्था में किस तरह की गड़बड़ी है और उसे ठीक करने के लिए वह क्या कर रही है। मौजूदा वित्त मंत्री द्वारा पिछले साल का बजट पेश करने के बाद इकॉनमी के अलग-अलग हिस्सों की उस पर जैसी प्रतिक्रिया मिली और जिस तरह वह लगातार अपनी बजट घोषणाओं में रद्दोबदल करने में जुटी रहीं, उससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विश्वसनीयता का संदेश शायद ही गया हो। टुकड़ों में राहतें देने और फैसलों में बार-बार संशोधन करने से लोगों में यह अंदेशा पैदा हुआ कि सरकार के फैसलों के पीछे अपना कोई ठोस तर्क नहीं है। लोगों की यह समझ गलत भी हो सकती है, लेकिन इसे सुधारने की कोई कारगर पहल वित्त मंत्री की ओर से नहीं दिखी। बहरहाल, पिछले वित्त वर्ष की इस आखिरी तिमाही के अंतिम हफ्ते में घोषित लॉकडाउन ने इकॉनमी को भीषण मंदी के चंगुल में फंसा दिया है, जिससे निकलने के लिए बाकी दुनिया से ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। 2008 की मंदी अभी सबकी याददाश्त में है, पर उस समय राहत की बात यह थी कि मंदी के ठीक पहले तक अर्थव्यवस्था चढ़ान पर थी और सरकार अपनी तरफ से पैसा झोंककर इकॉनमी को गति देने की हालत में थी। अभी के आंकड़े बता रहे हैं कि यह सुविधा इस बार सरकार के पास नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बस उसे समस्या को दरकिनार करने की, सारा दोष कोरोना या किसी और के मत्थे मढ़ने की कोशिशें छोड़कर यह स्वीकार करना होगा कि इकॉनमी के हर स्याह-सफेद का जिम्मा उसका है। फिर विशेषज्ञों की राय-सलाह से पिछली गड़बड़ियों को सुधार कर भविष्य की ओर कदम बढ़ाए जाएं।

एमएसएमई की नई परिभाषा लघु उद्योग को न सिर्फ नया स्वरूप देगा बल्कि नई पहचान भी देगा

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदलने के फैसले को लघु उद्यमियों ने न सिर्फ इस क्षेत्र के लिए बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एक अप्रतिम सौगात कहा है। इस क्षेत्र का कहना है कि एमएसएमई क्षेत्र लॉकडाउन से पहले से ही काफी समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में लॉकडाउन के दो-तीन महीनों ने तो एक तरह से कमर ही तोड़ दी। अब सरकार ने इस क्षेत्र की सुध ली है। उम्मीद है कि अगले 3-4 तिमाही में इसका असर दिखने लगेगा।

इस क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधियां जोर पकड़ेंगी

एमएमएमई क्षेत्र के उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करने वाला उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के अध्यक्ष डी. के. अग्रवाल का कहना है कि मध्यम दर्जे के उद्योग पहले से ही बेहतर काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए जो पहले परिभाषा तय की गई थी, उसमें 10 करोड़ रुपये का निवेश और 5 करोड़ रुपये का टर्नओवर था, जो कि काफी कम था। इसे बढ़ा कर 20 करोड़ रुपये का निवेश और 100 करोड़ रुपये का टर्नओवर का फार्मूला तय किया गया था। यह भी कम था और पीएचडीसीसीआई ने इसकी सीमा बढ़ाने के लिए आवाज भी उठायी थी। अच्छी बात है कि अब इस श्रेणी के उद्योग में 50 करोड़ रुपये का निवेश और 250 करोड़ रुपये के कारोबार को मान्यता दी गई है। इससे इस क्षेत्र में विनिर्माण की गतिविधियां खूब जोर पकड़ेंगी।

जीडीपी में भी होगी बढ़ोतरी

डी. के. अग्रवाल का कहना है कि इस समय बिना परिभाषा में विस्तार किये हुए ही देश के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 29 फीसदी का है। जबकि मध्यम दर्जे के उद्यमों के लिए 250 करोड़ रुपये के कारोबार और 50 करोड़ रुपये प्लांट एवं मशीनरी में निवेश का दरवाजा खुलेगा तो इस क्षेत्र में उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। इसका असर रोजगार पर और अंततः जीडीपी में बढ़ोतरी पर पड़ेगा।

एमएसएमई के लिए साहसिक आर्थिक सुधारों के लिए एक ऐतिहासिक दिन

फेडरेशन आफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (FISME) के सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज का कहना है कि आज का दिन MSME के लिए साहसिक आर्थिक सुधारों का एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। उनका कहना है कि कुछ ऐसे उद्योग हैं, जिसमें प्लांट एंड मेशिनरी तो काफी कम का होता है लेकिन उसके कच्चे माल काफी कीमती होते हैं। इनमें जेम्स एंड ज्वैलरी उद्योग आते हैं। इसका कच्चा माल काफी महंगा होता है लेकिन इसका निर्यात में भी भारी योगदान है। मंझोले उद्योग की परिभाषा में सुधार करने से अब इस क्षेत्र जैसे उद्योगों को काफी फायदा होगा।

3-4 तिमाही में दिखेगा असर

भारद्वाज का कहना है कि आज जो फैसला हुआ है, इसका असर दिखने में तीन से चार तिमाही का वक्त लगेगा। उनका कहना है कि लॉकडाउन से पहले भी करीब 5 लाख लघु उद्यम स्ट्रेस्ड थे। लॉकडाउन में उनकी संख्या और बढ़ेगी। लेकिन अब सरकार ने इनकी सुध लेगी तो उम्मीद की जा रही है कि धीरे-धीरे हालात बदलेंगे।

वैश्विक संकेतों और हाजिर मांग के कारण कच्चा तेल वायदा कीमतों में तेजी

नयी दिल्ली। एजेंसी

मजबूत वैश्विक संकेतों के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को कच्चे तेल की कीमत 98 रुपये की तेजी के साथ 2,844 रुपये प्रति बैरल हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून डिलिवरी वाले कच्चे तेल की कीमत 98 रुपये यानी 3.57 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,844 रुपये प्रति बैरल हो गई। इसमें 5,718 लॉट के लिए कारोबार हुआ। कच्चा तेल के जुलाई माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 95 रुपये यानी 3.41 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,881 रुपये प्रति बैरल हो गई। इसमें 231 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने के कारण कच्चातेल वायदा कीमतों में तेजी आई। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चातेल की कीमत 2.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 37.60 डालर प्रति बैरल हो गयी जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 40.18 डॉलर प्रति बैरल हो गई।

कूड़े से बिजली बनायेगा एनटीपीसी का संयुक्त उपक्रम

इंदौर नगर निगम के साथ भी समझौता

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सरकारी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने कूड़े से बिजली बनाने के लिये पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के साथ एक संयुक्त उपक्रम स्थापित की है। कंपनी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। एनटीपीसी ने शेयर बाजारों को बताया कि एनटीपीसी लिमिटेड ने ईडीएमसी के साथ मिलकर एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड गठित की है। इसमें एनटीपीसी की 74 प्रतिशत और ईडीएमसी की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी ने कहा कि संयुक्त उपक्रम कूड़े से बिजली तैयार करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी ने इस तरह शहरी कचरे को ईंधन बना कर बिजली तैयार करने में कवास, वाराणसी, इंदौर और मोहाली के नगर निगमों के साथ सहयोग का समझौता किया है।

अंतिम वक्त में फिसला शेयर बाजार

सेंसेक्स 284 और निफ्टी 82 अंक चढ़कर बंद

मुंबई। एजेंसी

यह लगातार छठा कारोबारी दिन है जब शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरो वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 284 अंकों की बढ़त के बाद 34,109.54 के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स दिन के उच्च स्तर 34,488.69 को भी छुआ, लेकिन दोपहर बाद यह फिसल गया। यही हाल निफ्टी का भी रहा। आज 10,176.20 का स्तर देखने वाला निफ्टी महज 82.45 अंक चढ़कर 10,061.55 के स्तर पर बंद हुआ। अगर सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, प्रइवेट बैंक, रियलिटी और फार्मा हरे निशान के साथ बंद हुए जबकि आईटी और मेटल लाल निशान पर। निफ्टी टॉप गेनर की बात करें तो बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्लेइंडिया, आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक प्रमुख रहे तो वहीं विप्रो, इंडसइंड बैंक, जी लिमिटेड, एनटीपीसी, इन्फ्राटेल नुकसान के साथ बंद हुए।

2:16 बजे: शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। आईटी शेयरों को छोड़कर निफ्टी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। पीएसयू बैंक में 4.70 फीसद, प्राइवेट बैंक में करीब 4 फीसदी, रियल्टी में 3.88 फीसद, मेटल में 1.30 फीसद, ऑटो 1.18 फीसद और फाइनेशियल सर्विसेस इंडेक्स में 3.30 फीसद की तेजी दिख रही है। सेंसेक्स में अब बढ़त 559 अंकों की हो गई है और यह 34,385.02 के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी 168.70 (1.69%) अंकों की उछाल के साथ 10,147.80 के स्तर पर है।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे उछला

रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32 पैसे बढ़कर 75.04 के स्तर पर आ गया। घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक शुरुआत, एशियाई मुद्राओं की तेजी और डॉलर में कमजोरी के रुख से स्थानीय मुद्रा को मजबूती मिली। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 75.04 के स्तर पर खुला, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 32 पैसे की मजबूती दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 75.36 पर बंद हुआ था।

इंडिगो को चौथी तिमाही में 871 करोड़ रुपये का नुकसान

कोविड-19 के कारण उड़ानों पर प्रतिबंध की वजह से देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो को 31 मार्च को समाप्त पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 870.81 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ है। अंतिम तिमाही में हुए घाटे के कारण पूरे वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी को 233.68 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। एक साल पहले की तुलना में एयरलाइन का कुल राजस्व 16.41 प्रतिशत घटकर 8,634.62 करोड़ रुपये रह गया, जबकि कुल लागत 1.54 प्रतिशत बढ़कर 9,9243.93 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। इस कारण कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उड़ानों पर प्रतिबंध से विमान ईंधन के मद में उसकी लागत 3,341.94 करोड़ रुपये से घटकर 2,860.36 करोड़ रुपये रह गई।

ब्रिटानिया का चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 372 करोड़ रुपये

एफएमसीजी कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का बीते वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी (जनवरी-मार्च) की तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 26.53 प्रतिशत बढ़कर 372.35 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 294.27 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल परिचालन आय बढ़कर 2,867.70 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,798.96 करोड़ रुपये थी।

पीएनजीआरबी ने कहा एलएनजी पंप लगाने के नियमन के अधिकार नहीं

नयी दिल्ली। एजेंसी

तेल क्षेत्र के नियामक पीएनजीआरबी ने कहा है कि उसके पास एलएनजी पंप स्टेशन स्थापित करने के नियमन का अधिकार नहीं है और कोई भी कंपनी इस तरह के पंप देश में कहीं भी लगा सकती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) स्टेशन लगाने के बारे में आग्रह किया गया था। इस पर पीएनजीआरबी ने कहा कि वह जिस कानून के तहत कार्य करता है उसमें उसे केवल सीएनजी ईंधन केन्द्र लगाने और उनके लिये लाइसेंस जारी करने का अधिकार है। इसमें एलएनजी स्टेशनों के लिये नियमन ढांचे के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नियामक ने कहा है कि पीएनजीआरबी कानून सीएनजी स्टेशनों को लेकर व्यापक तौर पर बात करता है। इसमें शहरी गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने और उसका परिचालन करने की इच्छुक कंपनी को अधिकार देने का भी प्रावधन किया गया है। इस तरह का नेटवर्क सीएनजी स्टेशन स्थापित करने के लिये जरूरी भी है।'' पीएनजीआरबी ने अपने आदेश में कहा है, ''संबंधित कानून में सीएनजी स्टेशन के लिये नियामकीय रूपरेखा बताई गई लेकिन इसमें एलएनजी स्टेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।''

कच्चा तेल मौजूदा स्तर पर बना रहा, तो रुपया स्थिर रहेगा : एसबीआई चेयरमैन

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार का मानना है कि यदि कच्चे तेल के दाम मौजूदा निचले स्तर पर बने रहते हैं और राजकोषीय घाटा काबू में रहता है, तो रुपये में स्थिरता रहेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि अभी तक डॉलर के मुकाबले रुपया स्थिर है। उन्होंने कहा, ''यदि कच्चे तेल के दाम आज की स्थिति में बने रहते हैं, तो रुपये पर काफी कम दबाव रहेगा। हमारा सबसे बड़ा आयात या तो कच्चा तेल है या सोना। सोने का आयात लगभग शून्य है और कीमतों में गिरावट के चलते कच्चे तेल का आयात भी नीचे आया है। ऐसे में रुपया पर दबाव कम है। भविष्य में भी ऐसा रुख जारी रहने की गुंजाइश है।'' पिछले दो माह में रुपये में खास उतार-चढ़ाव नहीं आया है और यह 75-76 प्रति डॉलर पर बना हुआ है। ब्रेंट कच्चा तेल 39 डॉलर प्रति बैरल पर है जबकि भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल का दाम मंगलवार को 35 डॉलर प्रति बैरल पर था। कुमार ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि रुपये में स्थिरता रहेगी।

MCX : जिस कच्चे तेल पर होती है हाहाकार, उसमें आप सीधे करिए कारोबार

नयी दिल्ली। एजेंसी

कच्चा तेल, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक है। वे देश जो कच्चे तेल या क्रूड का उत्पादन करते हैं या फिर भारत जैसे वे देश जो बड़ी मात्रा में इसका आयात करते हैं उनकी अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल के दाम घटने या बढ़ने का काफी असर पड़ता है। कच्चे तेल को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जो कि लाखों साल पहले कार्बनिक पदार्थों के गलने से बना है और धरती के नीचे मिलता है। 19वीं सदी के मध्य में पेट्रोलियम की खोज होने तक जीवाश्म ईंधन का एकमात्र स्रोत कोयला था। आज पेट्रोलियम दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो जीवाश्म ऊर्जा में लगभग 40 प्रतिशत योगदान देता है। दुनिया भर के देशों की नजरें कच्चे तेल की कीमतों पर लगी रहती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आप बैठे-बैठे क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि भारत में कैसे आप क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग के जरिए अमीर बन सकते हैं।

MCX
India's No.1 Commodity Exchange

MCX देता है ट्रेडिंग का ऑप्शन

2003 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत के बाद से, भारत के कमोडिटी ट्रेडिंग मार्केट में 120 गुना की वृद्धि हुई है। अभी भी हमारे देश में कमोडिटी ट्रेडिंग में डेवलपमेंट की जबरदस्त संभावना है। आज भारत का अपना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) चांदी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। इस पर सोने, तांबे और प्राकृतिक गैस के अलावा कच्चे तेल में भी कारोबार होता है। यहीं से आप क्रूड ऑयल / कच्चे तेल में ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं।

ब्रोकर चुनना है जरूरी : एमसीएक्स में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ब्रोकिंग फर्म है। किसी एक ऐसी फर्म को चुन कर ट्रेडिंग शुरु की जा सकती है। मगर जिस ब्रोकर ब्रोकिंग फर्म को आप चुने वो एमसीएक्स पर रजिस्टर होना चाहिए।

रजिस्ट्रेशन : कच्चे तेल में ट्रेड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें ब्रोकिंग फर्म आपकी सहायता करेगी। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जरूरी डिटेल के साथ भरें और जरूरी दस्तावेज जमा करें। फॉर्म को जमा करने पर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

मिनिमम इनवेस्टमेंट : अलग अलग कमोडिटी के लिए अलग अलग निवेश राशि होती है। ये कीमत हर कमोडिटी के मूल्य के बेसिस पर होती है।

जरूरी फंड : आपको ब्रोकर को फंड देना होता है। यानी ट्रेड शुरू करने के लिए शुरुआत में ही कुछ फंड ट्रांसफर करना होता है। जब तक ये फंड न ट्रांसफर किया जाए ब्रोकर आपके लिए ट्रेड शुरू नहीं करेगा। आप ये पैसा डीडी, चेक या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ट्रेडिंग शुरू होगी।

ईईएसएल, गेल ने ट्राइजनरेशन परियोजनाओं के लिये सहमति पत्र पर किये दस्तखत

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की गेल और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ईईएसएल) ने देश में 'ट्राईजनरेशन' परियोजनाओं के विकास के लिये बुधवार को सहमति पत्र पर दस्तखत किये। 'ट्राइजनरेशन' एक ईंधन से एक ही साथ चीजों को ठंडा रखने, गर्माहट पैदा करने और बिजली उत्पादन की एक तकनीक है। सामान्य रूप से इस तकनीक का उपयोग प्राकृतिक गैस अधारित जनरेटरों में होता है। गैस आधारित जनरेटरों का उपयोग बिजली पैदा करने में किया जाता है। फ्लू गैस से निकलने वाली गर्माहट (हीट) को एकत्रित कर उसका उपयोग गर्म पानी या 'स्टीम' में किया जाता है। इसका उपयोग गर्मी पैदा करने या ठंडा करने के लिये चिलर में किया जा सकता है। ईईएसएल ने एक बयान में कहा कि इस सहमति पत्र का मकसद संयुक्त रूप से देश में 'ट्राइजनरेशन' कारोबार में अवसर तलाशकर दोनों कंपनियों के बीच एक राणनीतिक भागीदारी तैयार करना है। इस समझौते के तहत गेल और ईईएसएल संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे और अगर व्यवहारिक पाया गया तो दोनों कंपनियां ट्राइजनरेशन परियोजनाओं के लिये 50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम बनाएंगी। गेल के चेयरमेन और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहा, ''देश में खासकर छोटे उद्योगों, वाणिज्यिक क्षेत्रों और कार्यालय इमारतों में 'ट्राइजनरेशन' परियोजनाओं के लिये उल्लेखनीय बाजार है। यह कारोबार अभी शुरूआती चरण में है, इस गठजोड़ से पहले आगे बढ़ने का लाभ ठीक उसी तरह से मिल सकता है जैसा कि गेल को सिटी गैस कारोबार में हुआ था।'' सहमति पत्र पर गेल के कार्यकारी निदेशक (व्यापार और परियोजना विकास) शांतनु राय और ईईएसएल के कार्यकारी निदेशक (रणनीतिक वृद्धि) अमित कुमार ने वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये दस्तखत किये। इस मौके पर गेल के प्रमुख मनोज जैन और ईईएसएल के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार मौजूद थे।

एमएसएमईः 20 हजार करोड़ रुपये की ऋण सहायता, 50 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंजूरी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने चुनौतियों से जूझ रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) की मदद के लिये सोमवार को कुछ उपायों को मंजूरी दी। इन उपायों में ऋण नहीं चुका पा रहे एमएसएमई के लिये 20 हजार करोड़ रुपये की ऋण सहायता तथा फंड ऑफ फंड्स के जरिये 50 हजार करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी डालना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने इनके अलावा एमएसएमई की परिभाषा बदलने को भी मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने घोषित 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत इन उपायों और एमएसएमई की परिभाषा बदले जाने की घोषणा की थी। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि सीसीईए ने मध्यम उपक्रमों के लिये टर्नओवर की सीमा को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने को मंजूरी दे दी। इसके अलावा एमएसएमई निकायों के वर्गीकरण के लिये निर्यात से प्राप्त टर्नओवर को शामिल नहीं किया जायेगा। गडकरी ने कहा कि 20 हजार

करोड़ रुपये की ऋण सहायता से दो लाख एमएसएमई को लाभ होगा। इसके अलावा शेयरों के बदले 50 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने की योजना से एमएसएमई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने तथा अपनी क्षमता का विस्तार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपये का 'फंड ऑफ फंड' का भी गठन किया जाएगा। फंड ऑफ फंड का परिचालन मूल कोष और कंपनियों को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराने (डॉटर फंड) के माध्यम से किया जाएगा। मूल कोष (मदर फंड)का उपयोग अन्य माध्यमों से पूंजी आकर्षित करने में किया जाता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''आज की मंजूरी के साथ, आत्मनिर्भर भारत अभियान के संपूर्ण घटकों के कार्यान्वयन के तौर-तरीके व इसका खाका तैयार हो गया है। इससे एमएसएमई क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी।' एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने एक योजना 'पीएम-स्वनिधि' को मंजूरी दी जिसके तहत रेहड़ी-पटरी के विक्रेता 10 हजार रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इसे एक साल के दौरान मासिक किस्तों में चुकाया जा सकेगा। इस योजना से करीब 50 लाख लोगों को लाभ मिलने के अनुमान हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी-पटरी के विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करने के लिये एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना 'पीएम स्वनिधि - पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि' शुरू की है। जावड़ेकर ने कहा कि विक्रेता 10 हजार रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जो एक सात में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि एमएसएमई की परिभाषा में 14 साल बाद बदलाव किया गया है। निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने कहा कि कुल कारोबार से निर्यात के हिस्से को बाहर करने से एमएसएमई को वैश्विक बनने में मदद मिलेगी। इससे उन्हें निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। वित्तीय परामर्श कंपनी फिनडॉक ग्रुप के प्रबंध निदेशक (एमडी) हेमंत सूद ने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और ये बड़े पैमाने पर कुशल श्रम को रोजगार मुहैया कराते हैं। उन्होंने कहा, 'सरकार के द्वारा एमएसएमई को शेयर बाजारों में सूचीबद्धता की अनुमति देने के निर्णय से उन्हें लंबी अवधि में मदद मिलेगी।''

सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, चांदी के रेट हुए सस्ते

नई दिल्ली। एजेंसी

अनलॉक भारत में काफी दिन बाद सर्राफा बाजार खुले तो रौनक नजर आने लगी। 1 जून की शुरुआत से ही अनलॉक का पहला चरण शुरू हो चुका है। इसके चलते बाजार में भी असर नज़र आने लगा है। सोने और चांदी के दामों में आज लगातार तीसरे दिन भी गिरावट आई है। विदेशों में कमजोरी के रुख के बाद कारोबारियों ने अपने सौदों की कटान की जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को सोने की कीमत 0.42% की गिरावट के साथ

46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को चांदी की कीमत 71 रुपए की गिरावट के साथ 49,009 रुपए प्रति किग्रा रह गई।

सोने में गिरावट जारी

एमसीएक्स में सोना के जून महीने में डिलीवरी वाले कॉन्टैक्ट की कीमत 196 रुपए अथवा 0.42% की गिरावट के साथ 46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई जिसमें 28 लॉट के लिए कारोबार हुआ। सोना अगस्त माह में डिलीवरी वाले कॉन्टैक्ट की कीमत 60 रुपए अथवा 0.13% की गिरावट के साथ 46,498 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई जिसमें 15,044 लॉट के लिए कारोबार हुआ। न्यूयॉर्क में सोना 0.31इ की गिरावट के साथ 1,728.60 डॉलर प्रति औंस रह गया।

चांदी वायदा कीमतों में भी गिरावट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जुलाई माह में डिलिवरी वाले चांदी की कीमत 71 रुपए यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 49,009 रुपए प्रति किग्रा रह गई। इसमें 12,128 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसी प्रकार, चांदी के सितंबर माह में डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 62 रुपए यानी 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 49,797 रुपए प्रति किग्रा रह गई। इसमें 944 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार एक्सपर्ट ने कहा कि विदेशी बाजारों में कमजोरी के रुख के कारण मुख्यतः घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों पर दबाव रहा। इस बीच न्यूयॉर्क के अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत 0.30% की गिरावट के साथ 18.20 डॉलर प्रति औंस रह गई।

जीएसटी रिटर्न में विलंब शुल्क को समाप्त करने पर चर्चा करेगी -जीएसटी परिषद

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अगली बैठक में अगस्त 2017 से जनवरी 2020 की अवधि के लिये जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर लगने वाले विलंब शुल्क को माफ करने पर चर्चा करेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा, ''बीती अवधि (अगस्त 2017 से जनवरी 2020) के दौरान जीएसटी विलंब शुल्क माफ करने के मुद्दे पर जीएसटी परिषद की अगली बैठक में चर्चा होगी।' जीएसटी परिषद की अगली बैठक 14 जून को हो सकती है। सीबीआईसी ने कहा कि ज्अगस्त 2017 से जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत हुई है। ऐसी मांगें की जा रही हैं कि जिन रिटर्न को तब से ही (अगस्त 2017 से) दाखिल किये जाने की जरूरत है, उनके लिये विलंब शुल्क माफ कर दिया जाये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न संकट के मद्देनजर पहले ही फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 2020 के जीएसटी रिटर्न को दाखिल करने का समय जून 2020 तक बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। इस अवधि के लिये कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा। सीबीआईसी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिये विलंब शुल्क लगाया जाता है कि करदाता समय पर रिटर्न दाखिल करें।

डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे गिरकर 75.47 रुपये प्रति डॉलर पर बंद

मुंबई। एजेंसी

घरेलू शेयर बाजार में तेजी के रुख के बावजूद अन्तरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की हानि के साथ 75.47 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ।विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख, विदेशी निधियों का प्रवाह, व्यावसायिक गतिविधियों के फिर से शुरु होने और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने स्थानीय मुद्रा को समर्थन प्रदान किया लेकिन अभी भी अमेरिका -चीन व्यापार युद्ध सहित कई सारे जोखिम मौजूद हैं जिससे पहले चरण का समझौता प्रभावित हो सकता है।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 75.04 पर मजबूत खुला लेकिन बाद में आरंभिक लाभ लुप्त हो गया और कारोबार के अंत में रुपये की विनिमय दर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की हानि के साथ 75.47 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मंगलवार को यह 75.36 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान रुपये ने 75.04 के उच्च स्तर और 75.52 के निम्न स्तर को छुआ।

News यू केन USE

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगियों को देगा बढ़ी हुई पेंशन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना संकट के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। अब इन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ ने सोमवार को बताया कि परिवर्तित पेंशन को बहाल करने के लिए कुल 973 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें पेंशन के लिए 868 और एरियर के लिए 105 करोड़ रुपये हैं। ईपीएफओ पर फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने श्रमिकों की लंबे समय से जारी मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया। इसके तहत श्रमिकों को 15 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति मिल गई। अब तक परिवर्तित पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशनभोगियों को आजीवन कम पेंशन मिल रही थी। श्रम मंत्रालय ने कहा, ईपीएफओ-95 के तहत पेंशन भोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह एतिहासिक फैसला लिया गया है। ईपीएफओ के देशभर में करीब 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं।

जूम एप ने पेश किया अधिक सुरक्षा फीचरों वाला नया संस्करण

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वीडियो कांफ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम ने व्यक्तिगत जानकारियों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिये नये फीचरों के साथ अपने एप का नया संस्करण पेश किया है।कंपनी ने अपने सभी उपयोगकर्ताओं से इसका नवीनतम संस्करण अपडेट करने के लिये कहा है।सीईआरटी-इन के एक नये परामर्श में कहा गया है, 'जूम का नवीनतम संस्करण 5.0 जारी किया गया है, जो ऑनलाइन बैठकों के डेटा की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले फीचर एईएस 256-बिट जीसीएम एन्क्रिप्शन से लैस है।''सीईआरटी-इन का यह नया परामर्श पीटीआई-भाषा के पास भी है।उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये लगाये गये लॉकडाउन के मद्देनजर भारत समेत दुनिया भर में जूम एप का इस्तेमाल बढ़ा है। इस बीच कंपनी डेटा की सुरक्षा को लेकर विवादों में रही है।

एमएसएमई, कृषि क्षेत्र को ऋण के लिए एसबीआई ने अलग खंड बनाया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

परिचालन के क्षेत्र में एक बड़े पुनर्गठन के तहतभारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों के ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिएए एक अलग वित्तीय समावेशन एवं सूक्ष्म बाजार (एफआईएंडएमएम) विभाग बनाया है। एसबीआई ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस नए खंड के तहत बैंक मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को ऋण की पेशकश करेगा। बैंक ने कहा कि ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों की करीब 8,000 शाखाएं छोटे कारोबारियों और किसानों को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराएंगी। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा ग्रामीण, अर्द्धशहरी, शहरी और महानगर क्षेत्रों में मौजूदा 63,000 ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिये सेवा की गुणवत्ता सुधारने और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, ''आज एक महत्वपूर्ण दिन है। एसबीआई सभी खंडों में देश के नागरिकों के साथ खड़ा है। एफआईएंडएमएम के गठन का मकसद विभिन्न कारोबारी क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना और शाखाओं में ग्राहकों के साथ संपर्क बढ़ाना है।'' कुमार ने कहा कि एसबीआई की इस पहल का मकसद देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।

सेवा क्षेत्र गतिविधियों में मई में गिरावट, कंपनियां घटा रही हैं नैकरियां: सर्वे

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी 'लॉकडाउन' के कारण पूरे देश में मई महीने में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी से गिरावट आयी और दुकानों पर उपभोक्ताओं का जाना लगभग बंद रहा। इन सबके कारण कंपनियों ने नौकरियां घटानी शुरू कर दी हैं। एक मासिक सर्वे में बुधवार को यह कहा गया। आईएचएस मार्किट भारत सेवा कारोबार गतिविधि सूचकांक मई में 12.6 पर रहा। यह उत्पादन में फिर से बड़ी गिरावट को प्रतिबिंबित करता है। सर्वे में कहा गया है कि हालांकि मई का सूचकांक अप्रैल के 5.4 के रिकार्ड निचले स्तर से बेहतर है लेकिन इसके बावजूद यह स्तर 14 साल से जारी आंकड़ा संग्रह के दौरान नहीं देखा गया। यह देश भर में सेवा गतिविधियों में भारी गिरावट को बताता है।सर्वे के अनुसार आईएचएस मार्किट इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के 50 से अधिक अंक होने का अर्थ है गतिविधियों में विस्तार, जबकि इससे कम अंक कमी को बताता है। इसमें कहा गया है कि कारोबारी गतिविधियां बंद होने से उत्पादन में तीव्र गितरावट आयी और मांग की स्थिति खस्ताहाल रही। आईएचएस मार्किट के अर्थशास्त्री जो हेयस ने कहा, 'भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अभी भी लगभग ठहरी हुई हैं। नवीनतम पीएमआई आंकड़ों से पता चलता है कि मई में एक बार फिर उत्पादन में भारी

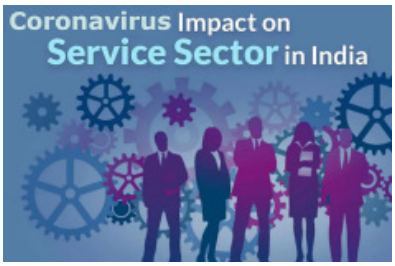

गिरावट हुई है।'' हेयस ने कहा कि सेवाओं की मांग में मई महीने में लगातार गिरावट रही। यह गिरावट घरेलू और वैश्विक बाजार दोनों जह देखी गयी। इसका कारण कारोबार का बंद होना और दुकानों पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या सामान्य स्तर से काफी नीचे रही। सर्वे में कहा गया है कि कमजोर मांग और आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण स्थिति के कारण रोजगार में लगातार कमी देखी गयी। समग्र पीएमआई उत्पादन सूचकांक भी मई में निजी क्षेत्र में व्यापार गतिविधियों में भारी गिरावट का संकेत देता है। यह सूचकांक सेवा और विनिर्माण उत्पादन को संयुक्त रूप से आकलित करता है।सर्वे के अनुसार समग्र पीएमआई उत्पादन सूचकांक मई में 14.8 रहा जो अप्रैल में 7.2 था। यह उत्पादन में हो रहे गिरावट को देखते हुए अप्रत्याशित नहीं है। हेयस ने कहा कि 2020 की पहली छमाही में आर्थिक उत्पादन में कमी तय है, ऐसे में यह साफ है कि कोविड-19 संकट से पहले के स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को आने में समय लगेगा। कोरोना वायरस संकट से पहले ही भारत में आर्थिक गतिविधियां नरम थी। इसका कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में संकट और उपभोक्ता मांग में कमी थी। देश की जीडीपी वृद्धि दर 2019-20 में 4.2 प्रतिशत रही जो 11 साल का न्यूनतम स्तर है। इससे पहले, सोमवार को मूडीज ने भारत की साख को कम कर निवेश के न्यूनतम स्तर पर कर दिया। इसका मुख्य कारण क्षमता के मुकाबले वृद्धि दर का धीमा होना और बढ़ते कज को लेकर जोखिम है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भरोसा जताया कि देश कोरोना वायरस महामारी से पार पा लेगा और सरकार की निर्णायक नीतियों से पटरी पर लौट आएगा।

विश्वबैंक ने कहा, दीर्घावधि की वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए वृहद नीतियां अपनाएं सभी देश

वाशिंगटन। एजेंसी

विश्वबैंक ने सभी देशों से कहा है कि वे दीर्घावधि की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए वृहद नीतियां अपनाएं। इसके साथ ही विश्वबैंक ने कहा कि देशों को कोरोना वायरस संकट के बीच स्वास्थ्य से संबंधित आपात स्थिति से निपटने के लिए लघु अवधि के उपाय भी करने की जरूरत है। विश्वबैंक का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि इस तरह के संकेत हैं कि 2020 में छह करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में चले जाएंगे। विश्वबैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मल्पास ने कहा कि जिस तेजी से कोविड-19 महामारी और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बंद किए जाने से दुनियाभर के गरीबों की बुरी हालत हुई है, वह आधुनिक समय के लिए बेहद असाधारण स्थिति है। मल्पास ने अपने प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावा रिपोर्ट से विश्लेषण वाले अध्ययन जारी करने के मौके पर संवाददाताओं से कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा, ''मौजूदा अनुमानों से पता चलता है कि 2020 में छह करोड़ लोग अत्यंत गरीब हो जाएंगे। हालांकि, इस अनुमान में और बढ़ोतरी की आशंका है।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी और अर्थव्यवस्था की बंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, खासकर गरीब देशों को। इस स्वास्थ्य संकट का बुरा दौर बीतने के बाद अब विकासशील देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को समुदाय को अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार को तेज करने के लिए कदम उठाना चाहिए। मल्पास ने कहा कि आज हमें जो नीतिगत विकल्प चुनना है उसमें निवेश को आकर्षित करने के लिए ऋण में अधिक पारदर्शिता, डिजिटल संपर्क में तेजी से आगे बढ़ना ओर गरीबों के लिए नकदी के सुरक्षा जाल का विस्तार करना शामिल है। इससे हम नुकसान को कम कर सकेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती से उबार सकेंगे।

सरकार ने गैर-नियमित क्षेत्रों के लिय कोकिंग कोयले की आपूर्ति की अवधि बढ़ायी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने इस्पात जैसे गैर-नियमित क्षेत्रों के लिये नीलामी में मंजूर कोयले की व्यवस्था के तहत कोकिंग कोयले की आपूर्ति की अवधि 30 साल तक बढ़ा दी है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कोल इंडिया प्रचूर मात्रा में उपलब्ध घरेलू कोयले को लेकर गैर-नियमित क्षेत्रों से संपर्क कर रही है। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को सोमवार को लिखे पत्र में कहा, ''सरकार ने गैर-नियमित क्षेत्रों को लेकर कोकिंग कोयले की व्यवस्था के लिये संशोधित अवधि को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गैर-नियमित क्षेत्र के लिये कोकिंग कोल की व्यवस्था की नीलामी के तहत 30 साल तक की मंजूरी दी जा सकती है।'' नीति के तहत नये ईंधन आपूति समझौते की अवधि अधिकतम 15 साल हो सकती है।

मूडीज़ ने भारत की रेटिंग घटाई

कहा 2020-21 में जीडीपी चार प्रतिशत घटेगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इनवेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को भारत की सावरेन (राष्ट्रीय) क्रेडिट रेटिंग को पिछले दो दशक से भी अधिक समय में पहली बार 'बीएए2' से घटाकर 'बीएए3' कर दिया। एजेंसी ने कहा है कि नीति निर्माताओं के समक्ष आने वाले समय में निम्न आर्थिक वृद्धि, बिगड़ती वित्तीय स्थिति और वित्तीय क्षेत्र के दबाव जोखिम को कम करने की चुनौतियां खड़ी होंगी। मूडीज़ का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में चार प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है। भारत के मामले में पिछले चार दशक से अधिक समय में यह पहला मौका होगा जब पूरे साल के आंकड़ों में जीडीपी में गिरावट आयेगी। इसी अनुमान के चलते मूडीज़ ने भारत की सरकारी साख रेटिंग को 'बीएए2' से एक पायदान नीचे कर 'बीएए3' कर दिया। इसके मुताबिक भारत के विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा की दीर्घकालिक इश्युअर रेटिंग को बीएए2 से घटाकर बीएए3 पर ला दिया गया है। 'बीएए3' सबसे निचली निवेश ग्रेड वाली रेटिंग है। इसके नीचे कबाड़ वाली रेटिंग ही बचती है। एजेंसी ने कहा, ''मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को भी बीएए2 से घटाकर बीएए3 कर दिया है। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी पी-2से घटाकर पी-3 पर ला दिया गया है।'' मूडीज का मानना है कि आने वाले समय में भारत के नीतिनिर्माता संस्थानों के समक्ष नीतियों को बनाने और उनके क्रियान्वयन की चुनौतियां खड़ी होंगी। ऐसी नीतियां जिनके क्रियान्वयन से कमजोर वृद्धि की अवधि, सरकार की सामान्य वित्तीय स्थिति के और बिगडने और वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते दबाव के जोखिम को कम करने में मदद मिले। मूडीज ने इससे पहले 1998 में भारत की रेटिंग को कम किया था। मूडीज़ का कहना है कि सुधारों की धीमी गति और नीतियों की प्रभावशीलता में रुकावट ने भारत की क्षमता के मुकाबले उसकी लंबे समय से चली आ रही धीमी वृद्धि में योगदान किया। यह स्थिति कोविड- 19 के आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी और यह इस महामारी के बाद भी जारी रहने की संभावना है। मूडीज़ ने इससे पहले नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाकर बीएए2 किया था। एजेंसी ने कहा कि नवंबर 2017 में भारत की रेटिंग को एक पायदान बढ़ाना इस उम्मीद पर अधारित था कि महवत्वपूर्ण सुधारों का प्रभावी क्रियानवरून किया जायेगा और इससे अर्थव्यवस्था, संस्थानों और वित्तीय मजबूती में लगातार सुधार आयेगा। तब से लेकर इन सुधारों का क्रियान्वयन कमजोर रहा और इनसे बड़ा सुधार नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार नीतियों का प्रभाव सीमित रहने के संकेत मिलते हैं।

विदेश से लौटने वाले नागरिकों को इस तरह से रोजगार दिलवाएगी सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारत लौटने वाले लोगों को भी देश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बन चुकी है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमित मंत्रालय (MSDE) को मिली है। मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और विदेश मंत्रालय (MEA) की साझेदारी इस योजना को लागू किया जाएगा।

सरकार ने शुरू की है एक नई पहल

वंदे भारत मिशन के तहत देश लौटने वाले नागरिकों की स्किल मैपिंग एक्सरसाइज़ का संचालन करने के लिए एक नई पहल SWADES (skilled workers arrival database for employment support) योजना की शुरूआत की गई है। इस Exercise के माध्यम से, स्किल इंडिया (Skill India) और अन्य मंत्रालयों का लक्ष्य कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है, जिसे भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। स्किल इंडिया एकत्रित जानकारी को देश में उपयुक्त प्लेसमेंट अवसरों (Placement opportunities) के लिए कंपनियों के साथ साझा करेगा। लौटने

वाले नागरिकों को एक ऐंऐंऐं स्किल फॉर्म भरने की आवश्यकता है और इसके बाद SWADES स्किल कार्ड जारी किए जाएंगे।

ऐसे मिलेगा इन्हें रोजगार

कौशल मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकारों, उद्योग संघों और नियोक्ताओं सहित प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा के माध्यम से उपयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने वाले नागरिकों के लिए ये कार्ड एक स्ट्रेटीजिक फ्रेमवर्क की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें MSDE का कार्यान्वयन संगठन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) भी सहयोग कर रहा है।

बनाया गया है एक विशेष पोर्टल

विभिन्न देशों से वापस लौटने वाले नागरिकों के आवश्यक विवरण को एकत्र करने के लिए www.nsdcindia.org/swades पोर्टल बनाया गया है, जिस पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म में व्यक्ति के कार्य क्षेत्र, नौकरी का शीर्षक, रोजगार, अनुभव के वर्षों से संबंधित विवरण एकत्र किए जा रहे हैं। फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी प्रश्न के जवाब एवं नागरिकों की हरसंभव सहायता के लिए एक टोल फ्री कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। अभी तक इस पर 4500 से ज्यादा पंजीकरण मिल चुके हैं। अब तक जितने आंकड़े एकत्र किये गए हैं, उसके आधार पर संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, कतर और सऊदी अरब ऐसे शीर्ष देश हैं जहाँ से सबसे ज्यादा भारतीय नागरिक वापस आये हैं। स्किल मैपिंग के अनुसार, यह नागरिक वहां मुख्य रूप से तेल और गैस, विमानन, निर्माण, पर्यटन और आतिथ्य, आईटी और आईटीईएस जैसे क्षेत्रों में कार्यरत थे। इन आंकड़ो से यह भी पता चला है कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा श्रमिक विदेशों से वापस लौटे हैं।

लाखों लोगों के लौटने के आसार

दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार के कारण एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ा है जिससे हजारों श्रमिक अपनी नौकरी गंवा रहे हैं और वैश्विक स्तर पर सैकड़ों कंपनियां बंद हो रही हैं। आगे के रोजगार की संभावनाओं के छोटे विकल्प के साथ, कई नागरिक भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के माध्यम से देश में वापस लौट रहे हैं। लाखों नागरिकों ने देश में वापस आने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मिशनों में पंजीकरण कराया है और अब तक 35,000 से अधिक लोग वापस देश लौट आए हैं। वंदे भारत का एक फोकस क्षेत्र खाड़ी क्षेत्र है, जहां इस समय 80 लाख से अधिक नागरिक रहते हैं।

BSNL ने लॉन्च किया 365 रुपए वाला प्लान, 365 दिन की वैधता वाले इस प्लान में कॉलिंग वैनीफिट्स के साथ रोजाना मिलेगा 2जीबी डाटा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

BSNL ने 365 रुपए का नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। रिचार्ज प्लान में रोजाना 250 मिनट के लिए वॉयस कॉल, डेली 2जीबी डाटा और रोजाना 100 एसएमएस का फायदा मिलता है। हालांकि, यह बेनेफिट्स 60 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं।

प्लान में मिलते हैं ये बेनेफिट्स

यह प्लान वॉयस कॉस 250 मिनट प्रति दिन की सीमा के साथ देता है। 250 मिनट प्रति दिन की फ्री वॉयस कॉल की सीमा पर पहुंचने के बाद बेस प्लान टैरिफ के मुताबिक चार्ज लागू होंगे। प्लान में रोजाना 2जीबी डाटा मिलता है और इस सीमा पहुंचने के बाद डेटा स्पीड घटकर 80Kbps हो जाती है। प्लान में 100 एसएमएस प्रति दिन और फ्री पर्सनलाइज्ड रिंग बैक टोन का भी ऑफर शामिल है। बेनेफिट्स की वैलिडिटी केवल 60 दिनों के लिए है, जबकि प्लान की वैलिडिटी 365 दिन की है। 60 दिन की बेनेफिट्स की अवधि खत्म होने के बाद ग्राहकों को वॉयस और डाटा वाउटर जोड़कर कॉल और डेटा की सुविधा को जारी रखना पड़ेगा।

इन सर्किल्स में हुआ लॉन्च

यह आंध्र प्रदेश, असम, बिहार-झारखंड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता-पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्व, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में उपलब्ध होगा।

लॉन्च किया 600 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान

BSNL ने 2,399 रुपए का नया प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में यूजर्स को 600 दिनों के लिए अनलमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलता है। कोई भी टेलीकॉम कंपनी इतना लंबा प्लान ऑफर नहीं करती है। हालांकि इस प्लान में कोई डाटा बेनिफिट नहीं है। यानी यह प्लान उन यूजर्स के लिए है जो इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें 100 एसएमएस रोजाना मिलेंगे। सबसे लंबी वैलिडिटी वाला यह प्लान 250 मिनट की डेली FUP लिमिट के साथ आता है।

विद्युत की तुरंत खरीद-बिक्री वाले बाजार की औपचारिक शुरूआत की

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बिजली मंत्री आर के सिंह ने बुधवार को औपचारिक रूप से देश भर में विद्युत की तुरंत खरीद-बिक्री वाले बाजार की शुरूआत की। इस बाजार में ग्राहक आपूर्ति से महज एक घंटा पहले बिजली खरीद सकेंगे। यह बाजार (रीयल टाइम मार्केट-आरटीएम) वितरण कंपनियों और निजी उपयोग के लिये ऊर्जा लेने वाले ग्राहकों को आपूर्ति से ठीक एक घंटा पहले एक्सचेंज से बिजली खरीदने की सुविधा देता है। बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार, ''बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री सिंह ने दिल्ली में देश भर में बिजली क्षेत्र में आरटीएम की वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये शुरूआत की।'' बिजली की तुरंत खरीद-बिक्री का बाजार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल) में एक जून को रात 12 बजे (रविवार की मध्य रात्रि) से आपूर्ति के लिये 31 मई की रात 10.45 मिनट पर परिचालन में आया। मंत्री ने कहा कि आरटीएम एक संगठित बाजार है जहां से देश भर में खरीदार और बिक्रेता जरूरत के हिसाब से तुरंत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश का बिजली बाजार दुनिया के गिने-चुने बाजारों में आ गया है, जहां इस प्रकार की व्यवस्था है। इस बाजार से बिजली के मामले में वास्तविक समय पर संतुलन को लेकर लचीलापन आएगा और उपलब्ध अधिशेष क्षमता का अनुकूलतम उपयोग हो सकेगा। आरटीएम बिजली बाजार को गतिशील बनाता है क्योंकि इसमें नीलामी हर 30 मिनट पर होती है। पूरे दिन में नीलामी के 48 सत्र होते हैं। यह बाजार वितरण कंपनियों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बड़े बाजार तक पहुंच को लेकर एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगा।राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर) पोसको बिजली एक्सचेंज के बीच समन्वय में स्वचालन को लेकर जरूरी सुविधा उपलब्ध करा रहा है ताकि आरटीएम की रूपरेखा के तहत तेजी से सौदा तथा उसका निपटान हो सके।

इस हफ्ते महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल

नई दिल्ली। एजेंसी

मई में देश में पेट्रोल, डीजल की मांग में सुधार देखने को मिला था। अब अनलॉक 1.0 में ढील मिलने से मांग बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और आने वाले दिनों में ओपेक की तरफ से होने वाले फैसला का असर इस पर पड़ेगा। ओपेक की इस हफ्ते बैठक होने वाली है। बैठक का मुख्य मुद्दा कच्चा तेल है। अगले कुछ महीनों के लिए उत्पादन में कटौती पर फैसला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो कच्चे तेल की कीमतों जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है, जिसका असर पेट्रोल-डीजल पर पड़ेगा।

प्रमुख महानगरों में इतना है दाम

आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 71.26, 73.30, 78.32 और 75.54 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की बात करें, तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 69.39, 65.62, 68.21 और 68.22 रुपये है।

जानिए आपके शहर में कितना है दाम

पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा।

प्रति दिन छह बजे बदलती है कीमत

बता दें कि प्रति दिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।

कैसे तय होती है तेल की कीमत?

विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है। देश में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स 69 फीसदी हो गया है, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। पिछले साल तक भारत में पेट्रोल-डीजल पर 50 फीसदी तक टैक्स था।

उच्चतम न्यायालय ने चेक की वैधता की अवधि से लॉकडाउन का समय हटाने की याचिका खारिज की

नयी दिल्ली। एजेंसी

उच्चतम न्यायालय ने चेक या डिमांड ड्रॉफ्ट की वैधता अवधि की गणना में कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के समय को निकालने की याचिका खारिज कर दी है। रिजर्व बैंक ने नवंबर, 2011 में इस बारे में निर्देश जारी किए। केंद्रीय बैंक ने चार नवंबर, 2011 को जारी निर्देश में कहा था कि एक अप्रैल, 2012 से बैंक चेक-ड्रॉफ्ट-पे ऑर्डर-बैंकर्स चेक का भुगतान उस पर अंकित तारीख के तीन महीने बाद नहीं कर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की। पीठ ने कहा कि याचिका में जो मुद्दा उठाया गया है वह नीतिगत फैसला है और अदालत इस तरह के मुद्दों पर कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में लॉकडाउन की अवधि को चेक की वैधता के समय में शामिल नहीं करने का निर्देश देने की अपील की थी। पीठने कहा कि हमारा विचार है कि यह रिजर्व बैंक द्वारा लिया गया नीतिगत फैसला है और न्यायालय इस पर कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता। पीठ ने इस याचिका को 'टिकने योग्य नहीं' मानते हुए खारिज कर दिया।

चंद्र ग्रहण आप देखने जा रहे हैं तो ये बातें काम की हैं

चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण विलक्षण खगोलीय घटना है जो प्रत्येक वर्ष घटित होती है। इन्हें खुली आंखों से सीधे देखना काफी हानिकारक माना जाता है। नंगी आंखों से ग्रहण देखने से आंखों की रोशनी पर इसका प्रभाव पड़ता है। आंखों की रोशनी मंद पड़ सकती है। वैसे जानकारों के अनुसार सूर्यग्रहण को कोरी आंखों से देखना नुकसानदायक होता है चंद्रग्रहण को नहीं। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण को देखने के लिए आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। आप किसी विशेष सोलर फिल्टर वाले चश्मे के साथ या उसके बिना भी चंद्र ग्रहण को बेहद आसानी से देख सकते हैं। आप अपने घर की छत, खुले मैदान या पार्क में खड़े होकर आंखों को ऊपर उठाकर सीधे चंद्रग्रहण देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण देखने के लिए आपको अपनी आंखों की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। चूंकि चंद्रमा की रोशनी आंखों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती है इसलिए आप बिना चश्मे के चंद्रग्रहण देख सकते हैं। चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य की रोशनी अत्यधिक तेज होती है जो आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान सोलर रेडिएशन के कारण आंखों के नाजुक ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिसके कारण आंखों की रेटिना पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जबकि चंद्रग्रहण के दौरान सोलर रेडिएशन का कोई खतरा नहीं रहता है और ना ही आंखें प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप ज्योतिष और धर्म में विश्वास रखते हैं तो चंद्र ग्रहण को देखने से बचें। चंद्र ग्रहण दिल, दिमाग और मन पर असर करता है। जैसे ज्वार-भाटा को चंद्र ग्रहण प्रभावित करता है उसी तरह भावनाओं के ज्वार पर भी असर डालता है।

- चंद्र ग्रहण के देखने के बाद और ग्रहण के दौरान आप उद्विग्न, विचलित या क्रोधित रह सकते हैं।
- चंद्र ग्रहण देखने से सिर में भारीपन की शिकायत हो सकती है।
- मानसिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति को चंद्र ग्रहण से दूर रखा जाता है।
- अगर आप बहुत भावुक किस्म के व्यक्ति हैं तो भी चंद्र ग्रहण देखने से आपकी भावनाओं में उतार-चढ़ाव आ सकता है।
- चंद्र ग्रहण अगर आपकी राशि के लिए अशुभ बताया जा रहा है तो फिर आधुनिक होने के चक्कर में इसे देखने का प्रयास न करें।

भारतीय मसालों का ग्रहों से संबंध जानिए इसमें छुपे सेहत के राज

भारत में हजारों तरह के मसालों का उत्पादन होता है। मसालों को हम सब्जी बनाने या अन्य कोई खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोग में लेते हैं। यह मसालें जहां हमारे स्वास्थ्य के उपयोगी हैं वहीं ये हमें ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाते हैं। तो आओ जानते हैं कि कौन सा मसाला किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है।

1. सूर्य : लाल मिर्च सूर्य और मंगल का मसाला है जो स्वाद की ग्रंथि को मजबूत कर रक्त को संचारित करता है। इसके अलावा काली मिर्च, सरसों, गुड़ और जौं आदि पर भी सूर्य का प्रभाव रहता है।

2. चंद्र : इलाइची चंद्र का मसाला है जो श्वास के रोगों में लाभदायक है। यह सुगंध पैदा करती है। इसके अलावा हींग भी चंद्र का मसाला है जो अपनी तीखी सुगंध और गुण से शरीर से वायु प्रकोप को दूर करती है। अर्थात पेट में गैस की समस्या है तो दूर हो जाएगी। इसके अलावा खोपरा जो अक्सर ग्रेवी मनाने में उपयोग में लिया जाता है।

3. मंगल : लाल मिर्च सूर्य और मंगल का मसाला है जो स्वाद की ग्रंथि को मजबूत कर रक्त को संचारित करता है। इसके अलावा रतन जोत सब्जियों में रंग और स्वाद पैदा करता है। इससे शरीर में साहस और शक्ति का संचार होता है। इसके अलावा दालचीनी, लाल मिर्च, अदरक, मैथी और मूंगफली (ग्रेवी में इसका उपयोग होता है) पर भी मंगल का प्राभव रहता है।

4. बुध : धनिया से पित्त संतुलित होता है। इसका रस किडनी को साफ करके मुत्राशय के रोग दूर करता है। इसके अलाला हींग और हरी इलायची पर भी बुध का प्रभाव माना गया है।

5. गुरु : हल्दी में घाव भरने की और विष प्रतिरोधक क्षमता होती है। बंगाली चना,

हल्दी, जौं आदि। इसके अलावा अपने रंग की वजह से सरसों को भी बृहस्पति का मसाला माना जाता है। इससे पित्त का संतुलन होता है और यह उर्जा प्रदान करता है।

6. शुक्र : जीरा शुक्र से साथ ही राहु का मसाला भी है। यह अम्लीय प्रभाव दूर करता है। यदि एसिडिटी हो गई है तो थोड़ा सा जीरा मसल कर फांककर चबाल लें। यह भूख भी बढ़ाता है। शुक्र और राहु खराब होने से यह समस्या होती है। इसके अलावा सौंफ भी शुक्र का मसाला है। यह भोजन को पचाता है और मुख के लिए भी लाभदायक है। भोजन करने के बाद अक्सर लोग यह खाते हैं। इसके अलावा खड़े नमक, दालचीनी, सौंफ, मटर और बींस पर भी शुक्र का प्रभाव माना गया है।

7. शनि : काली मिर्च शनि का मसाला है जो को कफनाशक है। यह पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करती है। इससे शनि प्रबल होता है। इसके अलावा लौंग में सिर दर्द और दांत का दर्द दूर करने की क्षमता होगी है। इसके अलावा तेल, काले तील, काली मिर्च, शहद और लौंग पर भी इसका प्रभाव माना गया है।

8. राहु : तेजपत्ता राहु का मसाला है। यह दर्दनाशक होता है। यह मसाले में सुगंध पैदा करता है। इसके अलावा जायफल त्वचा के रोग में लाभदायक तो है ही साथ ही यह अन्य कई रोग में भी लाभदायक होता है। दोनों ही मसाले को उपयोग सर्दी में ज्यादा करते हैं।

इसके अलावा लहसुन, काले चने, काबुली चने और मसले पैदा करने वाले पौधों पर राहु और केतु का अधिकार होता है। कुछ लोग जीरा पर भी राहु और केतु का अधिकार मानते हैं।

9. केतु : अजवाइन केतु का मसाला है जो वात नाशक होता है। यदि अजवाइन के साथ थोड़ा सा काला नमक मिलाकर फांक लिया जाए तो यह गैस की समस्या को दूर करता है। इसके इमली, अमचूर और तिल पर भी इसका प्रभाव माना जाता है। कुछ लोग जीरा पर भी राहु और केतु का अधिकार मानते हैं।

लाल किताब और पेड़ों का महत्व

लाल किताब के अनुसार हमारे जीवन में पेड़े, पौधे या वृक्षों का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि यह घर की उचित दिशा में नहीं लगे हैं तो यह आप पर सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं और नकारात्मक भी। दूसरा यह कि आपकी कुंडली के अनुसार यदि उचित पौधे नहीं लगे हैं तो भी यह आपने लिए नुकसान दायक हो सकते हैं। आजो जानते हैं लाल किताब में पेड़ों का महत्व।

सूर्य : सूर्य का वृक्ष तेजफल का वृक्ष होता है। कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठा है, उस भाव की ओर घर से बाहर या अंदर तेज फल का वृक्ष लगाना शुभ फलदायी होता है। शुक्र, राहु और शनि के वृक्ष इसके आसपास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पर्वतों पर उगने वाले पौधे, मिर्च, काली मिर्च, शलज़म, सूर्यमुखी का फूल, सरसों, गेहूं और विल्वमूल की जड़ पर भी सूर्य का अधिकार होता है।

चंद्र : पोस्त का हरा पौधा, जिसमें दूध हो या सभी दूध वाले वृक्ष या पौधे चंद्र के हैं। चंद्र यदि कुंडली में जिस भाव में बैठा हो तो उस भाव की दिशा अनुसार ऐसा पौधे लगाने चाहिए, लेकिन दूध वाले पौधे लगाने के लिए किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क जरूर करें। चंद्र के पौधे या वृक्ष के साथ शनि, राहु और केतु के वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा खोपरा, ठंडे पदार्थ, रसीले फल, चावल, खिरनी की जड़ और सब्जियों पर भी चंद्र का अधिकार रहता है।

मंगल : नीम का पेड़ साक्षात मंगल है। मंगल की दिशा दक्षिण है अतः नीम का वृक्ष कुंडली में मंगल की स्थित जानकर लगाना चाहिए और रोज उसमें जल चढ़ाते रहना चाहिए। नीम का पेड़ रोग और शोक दूर कर देता है। बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु के वृक्ष इस वृक्ष के आसपास नहीं होना चाहिए। वर्ना मंगल खराब हो जाएगा। इसके अलावा नुकीले वृक्ष, बरगद, अदरक, अनाज, जिन्सें, तुअर दाल, मूंगफली और अनंतमूल की जड़ पर मंगल का अधिकार रहता है।

बुध : केला, चौड़े पत्ते के पौधे या वृक्ष बुध के कारक है। यदि यह वृक्ष आपके घर के आसपास है तो किसी वास्तु शास्त्री या लाल किताब के विशेषज्ञ से संपर्क करें क्योंकि इसकी दिशा सही होना चाहिए। बुध को भी पूर्वदिशा का स्वामी माना जाता है। कुंडली में किस भाव में बुध बैठा है यह उस मान से तय होगा कि ये वृक्ष कहां लगाएं। बुध के वृक्ष या पौधों के साथ चंद्र के पौधे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आंधीझाड़ा की झाड़ी, विधारा की जड़, नर्म फसल, मूंग दाल, हरे मुंग की दाल और बैंगन पर भी बुध का अधिकार होता है।

गुरु : गुरु अर्थात बृहस्पति साक्षात रूप में पीपल का वृक्ष है। कुंडली में बृहस्पति शुभ हो और जिस भाव में बैठा है, मकान के उस हिस्से में या उस दिशा की ओर पीपल का वृक्ष लगाना शुभ माना जाता है। पीपल के पास शुक्र, बुध, शनि, केतु और राहु के वृक्ष नहीं होना चाहिए। इसके अलावा केले के वृक्ष, भारंगी/केले की जड़, खड़ी फसल, बंगाली चना और गांठों वाले पादप से जुड़े पौधे पर भी गुरु का अधिकार होता है।

शुक्र : कपास का पौधा और मनी प्लांट शुक्र का कारक है। कोई भी जमीन पर आगे बढ़ने वाली लेटी हुई बेल शुक्र की कारक है। यदि शुक्र खराब है तो घर में मनी प्लांट लगाएं। शुक्र अच्छा है तो भी लगाएं। शुक्र कच्ची भूमि का कारण है और आजकल घर में कच्ची भू?मी नहीं होती है। ऐसे में मनी प्लांट लगाना जरूरी हो जाता है। शुक्र के पौधों के पास कभी भी सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और राहु के पौधे या वृक्ष न लगाएं। इसके अलावा फलदार वृक्ष, फूलदार पौधे, गुलर, मटर, बींस, पहाड़ी पादप, मेवे पैदा करने वाले पादप और लताओं पर भी शुक्र का अधिकार होता है।

शनि : शमी, कीकर, आम और खजूर का वृक्ष शनि का कारक है। इनमें से शमी के वृक्ष को छोड़कर कोई सा भी वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। वायव दिशा शनि की होती है। शमी के वृक्ष को भी कुंडली की स्थिति जानकर ही उचित दिशा में लगाना चाहिए। इसके अलावा पादपों में जहरीले और कांटेदार पौधे, खारी सब्जियां, बिच्छोल की जड़ और तम्बाकू पर भी शनि का अधिकार होता है।

राहु : नारियल का पेड़, चंदन का पेड़, कुत्ता घास, कैक्टस और कांटे वाले सभी वृक्ष या पौधे राहु के कारक हैं। चंदन एवं नारियल के पेड़ को छोड़कर इन्हें घर में या आसपास कभी भी लगाना चाहिए। नारियल का पेड़ लगा है तो सूर्य, मंगल और चंद्र के पौधे या वृक्ष उसके आसपास नहीं होना चाहिए। नारियल यदि वास्तु अनुसार घर की उचित दिशा में लगा है तो ही शुभ फल देगा। इसके अलावा लहसुन, काले चने, काबुली चने और मसले पैदा करने वाले पौधों पर राहु और केतु का अधिकार होता है।

केतु : इमली का दरख्त, तिल के पौधे और केला केतु के कारक है। यदि केतु खराब हो तो इन पौधों को घर के आसपास लगाना घर के मालिक के बेटे के लिए अशुभ फल का कारक हो जाता है, क्योंकि कुंडली में केतु हमारे बेटे का कारक भी है। अतः इन वृक्षों को घर के आसपास न लगाएं। केतु की दिशा वायव्य है। केले का वृक्ष लगा है तो उसके पास मंगल और चंद्र के वृक्ष नहीं लगे होना चाहिए। इसके अलावा अश्वगंधा, लहसुन, काले चने, काबुली चने और मसले पैदा करने वाले पौधों पर राहु और केतु का अधिकार होता है।

वृक्ष के अन्य नियम : घर के पूर्व में बरगद, पश्चिम में पीपल, उत्तर में पाकड़ और दक्षिण में गूलर का वृक्ष शुभ होता है किंतु ये घर की सीमा में नहीं होना चाहिए। घर के उत्तर एवं पूर्व क्षेत्र में कम ऊंचाई के पौधे लगाने चाहिए। पौधारोपण उत्तरा, स्वाति, हस्त, रोहिणी एवं मूल नक्षत्रों में करना चाहिए। ऐसा करने पर रोपण निष्फल नहीं होता।

घर के दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र में ऊंचे वृक्ष (नारियल अशोकादि) लगाने चाहिए। इससे शुभता बढ़ती है। जिस घर की सीमा में निगुंडी का पौधा होता है वहां गृह कलह नहीं होती। जिस घर में एक बिल्व का वृक्ष लगा होता है उस घर में लक्ष्मी का वास बतलाया गया है। जिस व्यक्ति को उत्तम संतान एवं सुख देने वाले पुत्र की कामना हो, उसे पलाश का पेड़ लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा घर की सीमा में शुभ होता है।

घर के द्वार और चौखट में भूलकर भी आम और बबूल की लकड़ी का उपयोग न करें। कोई भी पौधा घर के मुख्य द्वार के सामने न रोपें। इससे जहां द्वार भेद होता है वहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता।

बांस का पौधा रोपना अशुभ होता है। जामुन और अमरूद को छोड़कर फलदार वृक्ष भवन की सीमा में नहीं होने चाहिए। इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है। आवासीय परिसर में दूध वाले वृक्ष लगाने से धनहानि होती है। महुआ, पीपल, बरगद घर के बाहर होना चाहिए। केवड़ा और चंपा को लगा सकते हैं। बैर, पाकड़, बबूल, गूलर आदि कांटेदार पेड़ घर में दुश्मनी पैदा करते हैं। इनमें जति और गुलाब अपवाद हैं। घर में कैक्टस के पौधे नहीं लगाएं।

सरकार ने 2020-21 के लिये धान के एमएसपी में 53 रुपये की वृद्धि की

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने फसल वर्ष 2020-21के लिये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सोमवार को 53 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इसके साथ ही तिलहन, दलहन और अनाज की एमएसपी दरें भी बढ़ायी गयी हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया यह फैसला किसानों को यह तय करने में मदद करेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ वे किन खरीफ फसलों की बुआई करें। धान मुख्य खरीफ फसल है और इसकी बुआई पहले ही शुरू हो चुकी है। अभी तक 35 लाख हेक्टेयर के रकबे में धान की बुआई की जा चुकी है।मौसम विभाग ने जून-सितंबर की अवधि के दौरान सामान्य मानसून का अनुमान लगाया है। नकदी फसलों में चालू फसल वर्ष (जुलाई से जून) के लिये कपास (मध्यम रेशे) का समर्थन मूल्य 260 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2020-21 के लिये 5,515 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। यह पिछले साल 5,255 रुपये प्रति क्विंटल था। कपास (लंबे रेशे) का समर्थन मूल्य 5,550 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,825 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। सरकार ने कृषि व संबंधित गतिविधियों के तीन लाख रुपये तक के अल्पावधि के कर्ज के भुगतान की तिथि भी अगस्त तक बढ़ा दी।केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, 'कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर, मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी है। धान (सामान्य) का एमएसपी को इस वर्ष के लिये बढ़ाकर 1,868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।''उन्होंने कहा कि धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को लागत पर 50 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित होगा। तोमर ने कहा कि 2018-19 में एमएसपी निर्धारित करने का नया सिद्धांत घोषित किया था। इसके तहत एमएसपी को लागत के कम से कम डेढ़ गुने के स्तर पर रखा जाता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिये एमएसपी की घोषणा इसी सिद्धांत के आधार पर की गयी।ग्रेड ए (बारीक किस्मत के) धान का एमएसपी 1,835 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,888 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि धान की सामान्य किस्त के उत्पादन की लागत 1,245 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि बारीक किस्त के धान की लागत 1,746 रुपये प्रति क्विंटल है। इन दोनों का एमएसपी लागत से 50 प्रतिशत अधिक है। अनाजों में बाजरे का प्रति क्विंटल एमएसपी 150 रुपये बढ़ाकर 2,150 रुपये, रागी 145 रुपये बढ़ाकर 3,295 रुपये प्रति क्विंटल तथा मक्के का एमएसपी 90 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये किया गया है। ज्वार संकर और ज्वार मालदंडी का एमएसपी 70-70 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर क्रमशः 2,620 रुपये और 2,640 रुपये तथा मक्के का 1,850 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। दलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये उड़द का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर छह हजार रुपये, तुअर (अरहर) का 200 रुपये बढ़ाकर छह हजार रुपये और मूंग का 146 रुपये बढ़ाकर 7,196 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। सरकार ने खाद्य तेलों के आयात को कम करने के लिये तिलहनों के एमएसपी में इस बार तेज वृद्धि की। सोयाबीन (पीला) का एमएसपी 170 रुपये बढ़कर 3,880 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी बीज का 235 रुपये बढ़कर 5,885 रुपये प्रति क्विंटल और मूंगफली का 185 रुपये बढ़कर 5,275 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।इनके अलावा, रामतिल (निगरसीड) का एमएसपी 755 रुपये बढ़ाकर 6,695 रुपये और तिल के बीज का 370 रुपये बढ़ाकर 6,855 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। सरकार के अनुसार, एमएसपी में की गयी इस वृद्धि के बाद किसानों को लागत की तुलना में बाजरा की खेती में 83 प्रतिशत, उड़द की खेती में 64 प्रतिशत, अरहर की खेती में 58 प्रतिशत और मक्के की खेती में लागत से 53 प्रतिशत अधिक आय प्राप्त होने के अनुमान हैं। इनके अलावा अन्य फसलों पर किसानों को लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक आय के अनुमान हैं।

वीरेंद्र नाथ दत्त को नेशनल फर्टिलाइजर्स के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन एफ एल) ने कहा कि वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वीरेंद्र नाथ दत्त, कंपनी में निदेशक (विपणन) के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए है। एनएफएल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ''कंपनी के निदेशक (विपणन) वीरेंद्र नाथ दत्त ने कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है।''बयान के अनुसार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से एमबीए, दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ओएनजीसी जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव है। एनएफएल में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, वह गेल (इंडिया) लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक थे। वहां वह कॉरपोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन कारोबार के प्रभारी थे। वे महानगर गैस लिमिटेड, मुंबई के बोर्ड में निदेशक भी रह चुके हैं। वर्ष 1995 में गेल इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले दत्त ने ओएनजीसी में भी 10 साल तक कार्य किया है।

अनाज, दाल, प्याज आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे, दो अध्यादेश मंजूर

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके। उम्मीद है कि इससे इन वस्तुओं का व्यापार मुक्त तरीके से किया जा सकेगा और इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सहायता) अध्यादेश, 2020' को भी मंजूरी दी। सरकार ने किसानों की स्थिति को, प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के सामने सशक्त बनाने के लिए मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 पर 'किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते' को भी मंजूरी दी। कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ' इससे कृषि क्षेत्र की सूरत बदलेगी और इसके साथ-साथ भारत के किसानों की मदद करने की दिशा में इसका दूरगामी प्रभाव होगा।'' उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन से अत्यधिक विनियामकीय हस्तक्षेप के संबंध में निजी निवेशकों को आशंकायें खत्म होंगी। तोमर ने कहा कि 'कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020' राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के अहाते के बाहर अवरोध मुक्त अंतर-राज्य और अन्य राज्यों के साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा, ''यह देश में व्यापक रूप से विनियमित कृषि बाजारों को खोलने का एक ऐतिहासिक कदम है।'' तोमर ने कहा कि मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश, 2020 ' पर किसानों के (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते से किसान, किसी प्रकार के शोषण के भय के बिना, प्रोसेसर, एग्रीगेटर, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि से समान स्तर पर जुड़ने के लिए सशक्त होंगे। ये प्रस्ताव कोविड-19 के प्रसार को थामने के लिए लगाये गये लॉकडाऊन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का हिस्सा हैं।

ताजा सौदों की लिवाली से ग्वारसीड वायदा कीमतों में तेजी

नयी दिल्ली। एजेंसी

हाजिर बाजार में मजबूती के रुख के कारण सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को ग्वारसीड की कीमत 48 रुपये की तेजी के साथ 3,562 रुपये प्रति 10 क्विन्टल हो गई। एनसीडीईएक्स में ग्वारसीड के जून माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 48 रुपये अथवा 1.37 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,562 रुपये प्रति 10 क्विन्टल हो गई जिसमें 24,010 लॉट के लिए कारोबार हुआ। ग्वारसीड के जुलाई माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 50 रुपये अथवा 1.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,578 रुपये प्रति 10 क्विन्टल हो गई जिसमें 20,610 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार सूत्रों के अनुसार, उत्पादक क्षेत्रों से मामूली आपूर्ति के कारण हाजिर बाजार में मजबूती के रुख को देखते हुए सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में ग्वारसीड कीमतों में तेजी आई।

टिड्डी नियंत्रण नीति केवल रासायनिक स्प्रे पर केंद्रित है: कृषि विशेषज्ञ

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में तीन दशक के रेगिस्तानी टिड्डी दल के सबसे बड़े प्रकोप के बीच एक कृषि विशेषज्ञ का मानना है कि इस पर नियंत्रण के लिए मात्र रासायनिक छिड़काव पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा और इस कीट की रोकथाम के अन्य प्राकृतिक तरीकों की अनदेखी की जा रही रही है। टिड्डियों ने - राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे पांच राज्यों को प्रभावित किया है - और केंद्र ने सीमावर्ती राज्यों को चेतावनी जारी की है। केंद्र की योजना ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर हवाई स्प्रे को बढ़ाने की है। हरियाणा स्थित कुदरती खेती अभियान के सलाहकार राजिंदर चौधरी ने एक बयान में कहा, 'कीटनाशकों के हवाई मार्ग से छिड़काव के ज्ञात दुष्प्रभावों के बावजूद, सरकार की टिड्डी नियंत्रण नीति केवल रासायनिक स्प्रे पर केंद्रित है और अन्य गैर-रासायनिक उपायों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है।' उन्होंने इस संबंध में कृषि मंत्रालय में एक ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी दुष्प्रभावों के टिड्डियों को नियंत्रित करने के संदर्भ में, भारत और विदेश के विशेषज्ञों द्वारा कई प्रभावी गैर-रासायनिक उपचार सुझाए गए हैं, जिसमें तेलंगाना के एक पद्म श्री पुरस्कार विजेता, जैविक खेती करने वाले किसान चिंताला वेंकट रेड्डी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चिंताला ने जैविक और गैर-रासायनिक तरीकों के माध्यम से टिड्डियों के नियंत्रण के लिए सरकार को सुरक्षित और प्रभावी उपाय बताये हैं। चौधरी ने कहा कि अगर रासायनिक तरीकों को एक साथ पूरा छोड़ा नहीं जा सकता है, तो कम से कम आबादी वाले क्षेत्रों में और जल भराव वाले क्षेत्रों के करीब, सरकार को रासायनिक उपायों को अपनाने के बजाय सुरक्षित गैर-रासायनिक उपायों को अपनाना चाहिये। गैर-रासायनिक उपायों में से कुछ के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा कि टिड्डे जो रात के दौरान यात्रा या भोजन नहीं करते हैं। उन्हें पकड़ कर एकत्रित किया जा सकता है और उन्हें पोल्ट्री फीड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस पद्धति की आर्थिक और भौतिक व्यवहार्यता स्थापित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक रात में 10 क्विंटल टिड्डे को पकड़ सकता है और मुर्गी और बत्तख के चारे के रूप में उपयोग कर सकता है, जिससे टिड्डियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। चौबीस घंटों के भीतर टिड्डियों को नियंत्रित करने का एक अन्य तरीका अलसी के तेल, खाद्य सोडा / सोडियम बाइकार्बोनेट और लहसुन का निचोड़, जीरा और नारंगी के अर्क का छिड़काव करना है। इस मिश्रण का फसलों पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। उन्होंने कहा कि टिड्डियों के चक्र को समझते हुए इसका समय पर उपयोग किया जा सकता है और उपलब्ध परजीवी कवक का उपयोग किया जा सकता है जो टिड्डों को मार सकता है। इसके अलावा, टिड्डियों को, फसलों पर किसी ऐसी चीज का छिड़काव करके भी नियंत्रित किया जा सकता है जो वनस्पति पदार्थ को अखाद्य बनाता हो। चिंताला ने पृथ्वी से चार फीट नीचे से 30-40 किलोग्राम मिट्टी लेकर इसे 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोलकर 10-20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाना चाहिये। पानी को तब छानकर फसलों पर छिड़का जाना चाहिए। यह सभी वनस्पतियों को टिड्डियों के लिए अखाद्य बना देगा। यह रेतीला-पानी एक सामान्य स्प्रे पंप के साथ छिड़का जा सकता है। टिड्डी का खतरा खत्म होने के बाद, सादे पानी के साथ फसल पर छिड़काव करने से पत्तियों से रेत की परत हट जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शोर मचाना, टिड्डियों के झुंड के रास्ते पर 50 फुट ऊँचा जाल लगाना या झुंडो के बीच से विमान उड़ाने जैसे उपायों के जिए बड़ा नुकसान बचाया जा सकता है।

कोरोना लाया एक और मुसीबत

एक-तिहाई छोटे कारोबार बंद होने के करीब

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

लॉकडाउन के पांचवे चरण के साथ ही UNLOCK-1 की शुरुआत हो गई है। मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि एक-तिहाई (हर तीन में से एक) से अधिक छोटे और मध्यम कारोबारों में रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे ये बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईएमओ) ने 9 अन्य उद्योग संस्थाओं के साथ मिल कर एक सर्वे किया है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कि एक-तिहाई से ज्यादा छोटे और मध्यम उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। एआईएमओ के सर्वे में एमएसएमई, स्व-नियोजित (Self Employed), कॉर्पोरेट सीईओ और कर्मचारियों से 46,525 जवाब मिले। यह सर्वे 24 मई से 30 मई के बीच ऑनलाइन किया गया।

रिकवरी की उम्मीद नहीं

सर्वे में शामिल 35 फीसदी एमएसएमई और 37 फीसदी स्वरोजगार उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके कारोबार में रिकवरी की उम्मीद नहीं है। वहीं 32 फीसदी

एमएसएमई ने कहा कि उनकी रिकवरी में छह महीने लगेंगे। सिर्फ 12 फीसदी ने तीन महीने से कम समय में रिकवरी की उम्मीद जताई। अच्छी बात ये रही कि कॉर्पोरेट सीईओ की तरफ से कारोबार के लिए बेहतर आशा जताई गई। कॉर्पोरेट सीईओ ने 3 महीनों में रिकवरी की बात कही। एआईएमओ के पूर्व प्रेसिडेंट केई रघुनाथन के अनुसार ऑपरेशन में गिरावट और भविष्य में मिलने वाले कारोबारी ऑर्डर को लेकर अनिश्चितता छोटे और मध्यम उद्यमों की सबसे बड़ी चिंता है।

पूरी तरह कोरोना जिम्मेदार नहीं

रघुनाथन कहते हैं कि व्यवसायों के बंद का पूरा कारण कोरोना महामारी नहीं सकती है। सर्वे शामिल लोगों को पिछले तीन सालों में पहले से ही कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें नोटबंदी, जीएसटी और अर्थव्यस्था में चल रही मंदी शामिल है। उनके अनुसार उनके लोन बढ़े होंगे और अब कोरोना ने ताबूत में अंतिम कील का काम कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के बाद से इतने बड़े पैमाने पर व्यापारों को बर्बाद होते नहीं देखा देखा गया। भारत में सबसे कठिन लॉकडाउन में से एक लगाया गया था, जिसमें 17 मई को समाप्त होने वाले तीसरे चरण के बाद आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी ढील दी गई।

कितने फीसदी कारोबार रहे अछूते

एआईएमओ के सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि केवल 3 प्रतिशत एमएसएमई, 6 प्रतिशत कॉर्पोरेट्स, और 11 प्रतिशत स्व-नियोजित उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे मौजूदा स्थिति से अप्रभावित रहेंगे और अच्छा काम करना जारी रखेंगे। इसकी वजह है लॉकडाउन के दौरान उनका आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगा होना। एमएसएमई, जिनकी संख्या 6 करोड़ से अधिक हैं और इनमें करीब 11 करोड़ लोग लगे हैं, इंटरनल भंडार कम होने और मांग घटने की वजह से दबाव में हैं। एमएसएमई सेक्टर देश के कुल विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत, 40 प्रतिशत निर्यात और राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है।

अप्रैल-मई में 52.62 लाख EPFO सदस्यों का केवाईसी हुआ अपडेट

नई दिल्ली। एजेंसी

ईपीएफओ ने अप्रैल-मई की अवधि के दौरान अपने 52.62 लाख ग्राहकों का केवाईसी विवरण अपडेट किया। इस अपडेशन में 39.97 लाख ग्राहकों के लिए आधार, 9.87 लाख ग्राहकों के लिए मोबाइल (यूएएन एक्टिवेशन) और 11.11 लाख ग्राहकों के लिए बैंक अकाउंट अपडेट शामिल है। यह जानकारी श्रम मंत्रालय ने दी है। केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) एक बार की प्रक्रिया है, जो सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) को केवाईसी विवरण के साथ ग्राहकों की पहचान के सत्यापन में मदद करती है।

ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अप्रैल और मई 2020 के महीने में अपने 52.62 लाख ग्राहकों के लिए ख्म्ण डेटा अपडेट किया है। ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान भी ग्राहकों के विवरण को बड़े पैमाने पर सुधारा है। पिछले दो महीनों में 4.81 लाख नाम, 2.01 लाख जन्मतिथि और 3.70 लाख आधार संख्या के सुधार हुए। एक ओर लॉकडाउन के दौरान कार्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने और दूसरी ओर ग्राहकों के लिए केवाईसी अपडेशन में लगे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने करने के लिए, ईपीएफओ ने कार्य-घर और सरलीकरण की रणनीति अपनाई। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को केवाईसी को अपडेट करने और विवरणों को सुधारने का काम सौंपा गया था, जिससे पेंडेंसी लगभग दिन-प्रतिदिन कम हो गई। केवाईसी अपडेशन सदस्य को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। इसने क्लेम सेटलमेंट, ईपीएफ एडवांस, पीएफ ट्रांसफर और पेंशन प्रोसेसिंग के लिए समय में कटौती करके, ईपीएफओ को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से दोनों तरह से सेवा प्रदान करने में मदद की है।

e-NPS सब्सक्राइबर को जल्द मिलने वाली है यह सुविधा, PFRDA ने दिया प्रस्ताव

नई दिल्ली। एजेंसी

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने e-NPS सब्सक्राइबर्स के लिए ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए एनपीएस से एक्जिट करने का अतिरिक्त विकल्प देने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में e-NPS अकाउंट खोला जा सकता है लेकिन उसे बंद करने की कोई ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। PFRDA ने हालिया सर्कुलर में कहा है कि ऱ्इए से बिना किसी दस्तावेज के झंझट के NPS अकाउंट को ऑनलाइन खोलने में मदद मिलती है। इसीलिए e-NPS सब्सक्राइबर्स को ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए एनपीएस से एक्जिट होने का अतिरिक्त विकल्प देने का निर्णय किया गया है। पीएफआरडीए ने कहा है कि यह विकल्प समय से पहले एनपीएस अकाउंट बंद कराने और सामान्य तरीके से एक्जिट करने वाले दोनों के लिए लागू होगा। सर्कुलर में कहा गया है कि यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। मौजूदा व्यवस्था के तहत e-NPS सब्सक्राइबर को अकाउंट को बंद कराने के लिए बैंक में जाना पड़ता है। पीएफआरडीए के सर्कुलर के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था के तहत e-NPS से ऑनलाइन एक्जिट संभव हो सकेगा।

सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज (CRAs) को बैंकों के साथ मिलकर ऑनलाइन 'e-NPS exit functionality' की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करने को कहा गया है। वहीं, एनपीएस सब्सक्राइबर्स की मौत से जुड़े क्लेम का ऑफलाइन निपटारा एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।

क्या है e-NPS

e-NPS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एनपीएस खाता खोल सकता है या पहले से मौजूद एनपीएस खाते में अंशदान कर सकता है। इस योजना में डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए अंशदान किया जा सकता है। हालांकि, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल Atal Pension Yojana में निवेश के लिए नहीं किया जा सकता है।

हमारे अतिथि

✍श्री ब्रजेश गांधी

कोरोना काल

विध्वंस से नवसर्जन का मौका

कोरोना कल की देश काल परिस्थिति ने अगर कीसिका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किया है तो वह छोटा उद्योगपति है, चाहे वो छोटी मोटी उत्पादन ईकाई चलता हो या फिर खेरची ता थोक में व्यापार करता हो, उन सभी साथियों के लिए पिछले दो महीने तो कठिन थे ही आने वाले पांच छह महीने भी बहुत कठिन रहने वाले है। लॉकडाउन के दौरान ना उत्पादन हुआ, ना माल बिका, ना कोई पेमैंट आया, लेकिन उस तो कर्मचारी की तनख्वाह करना पड़ी, बिजली बिल का भुगतान करना पड़ा, ब्याज, किराए जैसे अगीनित स्थाई खर्च़ से रूबरू होना पड़ा। ऐसे में स्वाभाविक है कि हम सभी की मनोदशा काफी अस्थिर है, अभी आगे आने वाला कल हमें आर्थिक चुनौतियों के दौर में ले जाने वाला है। कुछ के पास आर्थिक चुनौतियां होगी तो कुछ मजदूरों की कमी से परेशान रहेंगे, कुछ के बाजार का चलन ही बदल जाएगा, तो कुछ एक को शायद बदले हुवे परिपेक्ष में अपना व्यवसाय ही बदलना पड़े... इस संकट काल में ये याद रखें कि ये हालात हमारी वजह से नहीं आए हैं, खुद को या किसी ओर को दोष न दें, न हार अपमानित महसूस करें,रास्ता नज़र नहीं आएगा लेकिन हिम्मत न हारें,कम से कम खर्च करें, अपनी मानसिक परेशानियों को लेकर अकेले न रहें, दोस्तों से बात करें, परिवार में बात करें, किसी तरह का बुरा ख्य़ाल आए तो न आने दें...इस स्थिति से कोई नहीं बच सकता। धीरे धीरे खुद को पहाड़ काट कर नया रास्ता बनाने के लिए तैयार करें। हमें हर हाल में जीना है, कल के लिए। अभी कल ही मेरे पास एक फोन आया उस सज्जन को आटा, मसाले का कारोबार चालु करना है, मेने उनसे पूछा आप अभी क्यों नया काम चालू करना चाहते हो तो उन्होंने बताया, उनका केटरिंग का बहुत बड़ा काम है, ओर इंदौर में प्रथम पाच केटरर में उनका नाम है, वो शादी कैसे कार्यक्रम में 1000 से 10000 लोगो का खाने कि व्यवस्था करते थे, लेकिन अब आने वाले साल भर तक तो ये मुमकिन नहीं होने वाला, उनके व्यापार में दो बच्चे भी साथ है, तो अब कुछ नया काम तो करना पड़ेगा।

हम में से कहीं लोगो को शायद इसे ऐसी परिस्थिति यो का सामना करना पड़ सकता है, तो मानसिक रूप से तैयार रहे। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं बल्कि उसे स्वीकार करें! कुछ परिवर्तन हमें सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगें। बाजार के नकारत्मक प्रवृत्ति से डरे नहीं क्युकी अर्थशास्त्र में कुछ परिमाण बड़े विचित्र होते है जिसकी गिनती कहीं नहीं होती, अर्थतंत्र के रिपोर्ट में हर चीज की गिनती होती है लेकिन लोगो के जुझारूपन की ओर नए उत्साह की, देश को पुनः आगे बढ़ाने की भावनाओं की गिनती नहीं होती है। वास्तव में तो वहीं सबसे बड़ा घटक है, पिछले दो महीने में घर पे रहकर हमने ने अपने आप में ऊर्जा का जो जबरजस्त संग्रह किया है, जब ये ऊर्जा का विस्फोट होगा तब अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री भी बिना सेनेटाइजर से हाथ धोए दांतो तले उंगली दबा लेंगे।

विध्वंस के बाद नवसृजन होता ही है, आफत के बाद अवसर आता ही है, रात के बाद सुबह होती ही है। तो आओ हम सब एक नए उत्साह ओर जुझारूपन के साथ हमारे काम में जुटे, एक दूसरे की मदद करे, अगर हमारा कोई साथी उसके कारोबार में कोई संकट से जूझ रहा है तो हम सब साथ आए ओर एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़े, शारीरिक दूरी जरूर बनाए रखे लेकिन दिल ओर मन से आपस में जुड़े रहे एक दुसरे की मदद करते रहे, मुझे पूरा विश्वास है कि करोना का ये हाहाकार बहुत ही जल्द करोना के मंगलकाल में परिवर्तित होगा, परेशानी बड़ी है, महामरी विकराल है इस लिए अभी लड़ाई जारी रखनी होगी ओर हमे सतर्कता बरतनी होगी, फिर करोना हारेगा। हमे हर हाल में जीतना होगा ओर जीतेंगे भी आने वाला कल हमारा होगा।

शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसंपदा ।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ?
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्
दुःखभाग्भवेत् ?
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः

- लेखक वरिष्ठ उद्योगपति, विचारक और उद्योग संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।